भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 645

03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लागू की गईं योजनाएं

645. श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नई पहलें, योजनाएं, कार्यक्रम और परियोजनाएं शुरू की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है, यदि हां, तो ऐसी क्या कमियां पाई गई हैं जो किसानों की आय को दोगुना करने में बाधा उत्पन्न करती हैं;

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इन नई पहलों, योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं से किसानों विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के जीवन की गुणवत्ता में किस हद तक सुधार हुआ है; और

(ङ) किसानों के कल्याण के लिए नई पहलों, योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है और इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): कृषि राज्य का विषय है, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों का समर्थन करती है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21,933.50 करोड़ रुपये (बीई) से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के दौरान 1,27,290.16 करोड़ रुपये (बीई) कर दिया है।

भारत में सभी किसानों के हित और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आरंभ की गई नई पहलें/योजनाएं/कार्यक्रम और प्लान निम्नलिखित हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
5. संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)
6. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
7. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
8. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
9. नमो ड्रोन दीदी
10. स्टार्ट-अप एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड (एग्रीश्योर)
11. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
12. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)
13. पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)
14. कृषि मशीनीकरण उप मिशन (एसएमएएम)
15. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
16. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएचएंडएफ)
17. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
18. कृषि वानिकी
19. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
20. कृषि विस्तार उप मिशन (एसएमएई)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन
29. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन
30. पीएम धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई)

इन सभी योजनाओं/कार्यक्रमों ने लघु एवं सीमांत किसानों सहित सभी किसानों को उनकी आय बढ़ाने में निम्नानुसार सहायता प्रदान की है:

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है, जिन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और संबद्ध मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं का लाभ उठा कर अपनी आय में दो गुना से अधिक की वृद्धि की है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई,2018-जून,2019 के संदर्भ में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 77वें दौर (जनवरी 2019 - दिसंबर 2019) के दौरान कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 (एनएसएस का 70वां दौर) में 6,426 रुपए से बढ़कर 2018-19 (एनएसएस का 77वां दौर) में 10,218 रुपए हो गई।

घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमानों की तुलना निम्नानुसार है:

क्षेत्र	विभिन्न अवधियों में औसत एमपीसीई (रु.)	
	2011-12 एनएसएस (68वां दौर)	2023-2024
ग्रामीण	1,430	4,122
शहरी	2,630	6,996
ग्रामीण एमपीसीई के प्रतिशत के रूप में अंतर	83.9	69.7

*****